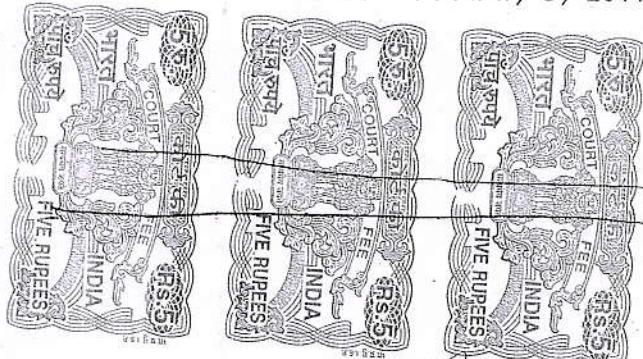


न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

R 1073. ३५/१५

प्र. क्र. निगरानी / 3 / 2014



- मृतक वारिस
प्रदीप
रमेश
मनमोहन
प्रमोद पुत्रगण स्व०श्री सरजुप्रसाद निवासी
ग्राम बम्हौरी रेगुवा तहसील व जिला ग्वालियर
म०प्र० प्रार्थी

बनाम

श्रीमती शारदाबाई पत्नि स्व०श्री विनायकराव
बेलापुरकर निवासी माता मड्डिया विजय टाकीज
रोड मोतीनगर वार्ड, सागर तहसील व जिला
सागर म०प्र० प्रतिप्रार्थी

म०प्र०भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय
अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 12/2012-13 अपील / 6 अ
में पारित आदेश दिनांकी 06.03.2014 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

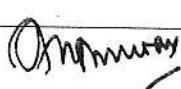
प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रतिप्रार्थीनी ने तहसीलदार सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/1990-91 अ-6 अ, में पारित आदेश दिनांक 01.04.1991 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी अपर तहसीलदार सागर द्वारा ग्राम बम्हौरी रेगुवा में स्थित पुराना सर्वे क्रमांक 124/1 एवं नया सर्वे क्रमांक 235, 308, 309, पुराना सर्वे क्रमांक 124/2 नया सर्वे क्रमांक 234/307, 124/3, नया सर्वे क्रमांक 306, पुराना सर्वे क्रमांक 125 नया 237 कुल रकवा 10.76 हेठो भूमि पर प्रार्थीगणों के पिता सरजू प्रसाद मौरसी कृष्ण के रूप में नाम अंकित था प्रार्थीगणों के पिता ने दिनांक 06.02.1991 में इस आशय का एक आवेदन पत्र अपर तहसीलदार सागर के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि विधि के अनुरूप प्रार्थी उक्त भूमि का अधिपत्य कृष्ण होने से उसे भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो चुके हैं इसलिये प्रार्थी के पिता को भूमि स्वामी घोषित किया जावे। प्रार्थीगणों के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 4/1990-91 में अ-6 अ दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 01.04.1991 के द्वारा भूमि स्वामी घोषित किया गया उक्त आदेश की जानकारी प्रतिप्रार्थी को राजस्व प्रकरण क्रमांक 108/2008-09 बी-121 में नायब

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1073—111/14

जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	<p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सागर द्वारा प्रक. 12/ अ-6/12-13 अपील में पारित आदेश दि. 6-3-2014 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कानुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी, सागर के आदेश दिनांक 6-3-2014 के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदिका द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील मेमो के साथ विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव शपथपत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है —</p>	

- भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)—धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 — पर्याप्त कारण होने से न्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।
- परिसीमा अधिनियम, 1963— धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)—धारा 47 — सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रुख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।
- भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)—धारा 47 — ग्राम में दूर रहने वाली वृद्ध, अशिक्षित महिला के प्रति विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु उदार रुख अपनाया जाना चाहिये।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता विधवा महिला है जिसके कारण तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर समाधान हो जाने से अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी—स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

Omnibus
सदस्य